

विश्व के 70 से अधिक ऐसे देश हैं जो स्वदेशी की भावना से खुद को विदेशी शासन से मुक्त करा सके। इनमें से अमरीका, चीन, जापान कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो आज विश्व की महाशक्तियों में गिने जाते हैं। प्रस्तुत लेख [भाई राजीव दीक्षित जी](#) के एक भाषण का लिखित स्वरूप है जिसमें मुख्य बिंदुओं की संक्षेप में चर्चा की गई है। आप इस व्याख्यान को स्वयं भाई राजीव जी के श्रीमुख से नीचे दिए गए लिंक पर भी सुन सकते हैं।

आज से 300 वर्ष पहले तक अमरीका का कोई अस्तित्व नहीं था। यह वो समय था जब अमरीका विदेशी शासन के चंगुल से खुद को मुक्त करने हेतु जूझ रहा था। ऐसी ही कहानी है जापान की जो कई वर्षों तक अमरीका, होलैंड और ब्रिटेन का गुलाम रहा और अंत में स्वतंत्र हुआ। हमारा पड़ोसी देश चीन जिसे अंग्रेजों ने अफीम के नशे में डुबो रखा था, खुद को 1949 में स्वतंत्र कराने में सफल हुआ। इन सभी राष्ट्रों में एक बात सामान्य थी और वो यह कि इन सभी देशों के स्वतंत्रता आंदोलनों की नींव थी स्वदेशी की भावना! चीन, जापान, अरब देशों में जिनका इतिहास पुराना है, सभी ने अपना तंत्र अपनी संस्कृति और अपनी भाषा में संजो कर रखा है।

यदि भारत की बात करें तो अंग्रेज़ शुरू से भारत के बारे में यह प्रचार करते आए हैं कि भारत सपेयों और लूटेरों का देश है। अंग्रेजों ने भारतवासियों को जीना सिखाया। भारत शुरू से ही गरीब और पिछड़ा देश था आदि। वहीं इन्हीं अंग्रेजों ने भारत के ऊपर लगभग 200 पुस्तकें लिखी हैं जो ब्रिटेन और स्कॉटलैंड में छपी थीं जिनमें बिल्कुल उल्टा लिखा था! उनमें लिखा है कि भारत बहुत अमीर देश है जिसका दुनिया की अर्थव्यवस्था में 43% योगदान है, भारत जैसा उन्नत देश पूरे विश्व में नहीं है आदि। उनकी यह बात ही सत्य है क्योंकि भारत अगर ऐसा देश न रहा तो अंग्रेज़ यहाँ कभी नहीं आते!

आज से 300 साल पहले तक पूरे यूरोप, अमरीका, जापान और चीन का कुल वार्षिक उत्पादन 5% भी नहीं था जबकि भारत का कुल वार्षिक उत्पादन पूरी दुनिया में 33% था! पूरी दुनिया की कुल आमदनी का 27% हिस्सा अकेले भारत के पास निर्यात करने से आ जाता था। भारतीय अपने यहाँ उत्पादित वस्तुओं को विदेशी बाज़ारों में बेचकर देश में सोना लेकर आते थे क्योंकि उस समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मुद्रा सोना हुआ करती थी। भारत में निर्मित कपड़ा हो या स्टील का जहाज़, सब बाहर सोने के दाम में बिकते थे! भारत एक औद्योगिक देश था जो सिर्फ सामान बेचा करता था लेकिन कभी बाहर से खरीदा नहीं करता था। एक औद्योगिक देश वह होता है जहाँ माल तैयार किया जाता हो जैसे आज के समय में चीन है और व्यापारी देश वह होता है जो दूसरे से सामान खरीदकर किसी तीसरे को बेचता हो जैसे आज के समय में ताइवान है।

जिन विदेशियों ने भारत के इतिहास का वर्णन अपने देशों में किया, उन्हीं के द्वारा भारत को दी गई संज्ञा है – ‘सोने की चिड़िया’। कोई भी देश इतना समृद्ध, स्वावलंबी और शक्तिशाली तब तक नहीं बन सकता जब तक उसमें स्वदेशी का दर्शन न छुपा हो! भारत में स्वावलंबन का केन्द्र थी उसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। भारत में आज से 150 साल पहले तक दो तरह की अर्थव्यवस्था होती थी – नगरीय तथा ग्रामीण। गाँव में उद्योग होते थे और वहाँ चीज़ें बनाई जाती थीं। शहरों में उन्हीं चीज़ों को बेचा जाता था। एक अंग्रेज़ इतिहासकार की मानें तो भारत के गाँव इतने आत्मनिर्भर थे कि वहाँ केवल एक ही चीज़ आयात होती थी और वह था नमक क्योंकि या तो नमक प्राकृतिक तौर पर पहाड़ों के रूप में उपलब्ध होता था जो हर जगह नहीं बनते थे और दूसरा, नमक समुद्र के जल से पैदा किया जाता था जो कि तटीय क्षेत्रों में ही संभव था। इसके अलावा एक इंसान के पैदा होने से मरने तक के बीच की सभी आवश्यकताएं गाँव में रहकर ही पूरी हो जाती थीं। नगर की सारी व्यवस्था गाँव पर निर्भर हुआ करती थी।

भारत के गाँव में हज़ारों किस्म के खाद्यान्न तथा उत्पाद पैदा किए जाते थे। एक दूसरे से वस्तुओं के आदान प्रदान से सब की आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। प्रत्येक गाँव में एक वैद्य होता था और हर 5 गाँव में एक शल्य चिकित्सक (Surgeon) होता था। वैद्य और चिकित्सक कभी कोई फीस नहीं लिया करते थे बल्कि जो लोग उनके यहाँ जाते थे वे कुछ भेंट दे आते थे जिससे उनका गुज़ारा चलता था। यह व्यवस्था इतनी सुगठित थी कि सामाजिक दायित्व वाले व्यक्तियों के लिए धन कमाना कभी प्राथमिकता नहीं होती थी और वे समाज कल्याण के लिए अपनी विद्या का निष्काम उपयोग कर पाते थे। इसी तरह 2-3 गाँव में एक हड्डी विशेषज्ञ होता था। हर घर में वरिष्ठ माताएँ प्रसूति कार्य में दक्ष होती थी और इस विद्या को वे अपनी भावी पीढ़ी को सौंपती थीं।

1868 से पहले तक भारत में 7 लाख से अधिक गुरुकुल थे जिनमें शास्त्रों के ज्ञान से लेकर जटिल विषय जैसे रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, धातु विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान आदि पढ़ाए जाते थे। ये पढाई आज की पढाई की तरह नौकरी ढूँढने के लिए नहीं होती थी बल्कि इन विद्याओं का उपयोग लोग अपने दैनिक व्यवहार से लेकर उद्योग तक में करते थे। एक और खास बात इस शिक्षा व्यवस्था में थी कि विद्यार्थी किसी एक विषय में दक्षता के लिए सम्पूर्ण समय दे सकते थे। उदाहरणार्थ, यदि आप रसायन शास्त्र पढ़ना चाहते हों तो शुरू से आपको ऐसे तैयार किया जाएगा कि आप अपनी सारी मानसिक ऊर्जा को एक विषय पर लगा सकते हैं उससे आप उस विषय में पूर्ण दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। गुरुकुल से आगे की शिक्षा के लिए भारत में 14000 उच्च शिक्षा केन्द्र और विश्वविद्यालय थे। 1868 से पहले तक भारत में साक्षरता दर 97% थी! गरीब-अमीर, राजा-रंक सबके लिए सामान शिक्षा व्यवस्था थी। ये गुरुकुल बिना प्रशासन की सहायता के लोगों द्वारा चलाये जाते थे। ये सभी आंकड़े अंग्रेज़ों के हैं जिनके यहाँ पहला स्कूल 1868 में खोला गया और वो भी केवल राजसी बच्चों के लिए। उनके विद्यालयों में सामान्य व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होता था!

भारत की अर्थव्यवस्था के केन्द्र में किसान होता था क्योंकि सारा का सारा मामला रोटी पर निर्भर होता है। चाहे गरीब हो या अमीर हर किसी की सबसे पहली आवश्यकता है रोटी! किसान खाने के लिए रोटी उगाता था, पहनने के लिए कपास उगाता था फिर इस कच्चे माल से कारीगर माल तैयार करते थे और फिर वही माल व्यापारियों द्वारा शहरों में बेचा जाता था। यह वो समय था जब भारत में कभी कोई भूख से नहीं मरता था। इसीलिए अंग्रेजों ने भारत के केन्द्र यानी किसान को बर्बाद किया। उन्होंने उस पेशे को खत्म करने की चेष्टा की जो कभी हमारे राष्ट्र का सबसे उत्तम पेशा होता था। हमारी सरकार इस दिशा में बहुत ठोस कदम उठा रही है! ये ठोस कदम किसानों को आबाद करने के लिए नहीं बल्कि बचे हुए किसानों को बर्बाद करने के लिए हैं! आप देख ही रहे हैं कि किस तरह FDI और विदेशी कंपनियों को खुली तूट के निमंत्रण दिए जा रहे हैं। हमारे अपने प्रधानमंत्री का कहना है कि भारत में 70% अधिक किसान हैं और वे अकुशल कारीगर हैं जिन्हें शहरों की ओर लाना पड़ेगा। यानी 2050 तक आपको देश में एक भी किसान, गाँव और भरा पेट नहीं मिलेगा!

मध्यकालीन भारत में कारीगरों का समाज में बहुत सम्मान होता था। उस समय श्रम अमूल्य होता था अर्थात् उसे आप धन देकर मोल नहीं ले सकते थे। अगर किसी को घर बनाना हो तो सारा गाँव उसकी सहायता करता था फिर जब किसी और को घर बनाना होता तो यह व्यक्ति उनकी सहायता करता। यही भाईचारा ग्रामीण जीवन के हर क्षेत्र जैसे विवाह, दाह संस्कार, विवाह आदि में होता जिसमें कभी भी श्रम खरीदा नहीं जाता था बल्कि सब आपस में एक दूसरे की सहायता करके कार्य को पूर्ण करते थे। इसमें धर्म, जाति, तबका आदि नहीं देखा जाता था! यही नहीं आज के आधुनिक समाज में जिन लोगों को हेय समझा जाता है जैसे हिजड़े, गणिकाएँ, चंडाल आदि; उन लोगों का भी समाज में महत्व और सम्मान था। जब किसी का विवाह होता था तो मंगल सूत्र पर पहले हिजड़े और गणिकाओं के यहाँ की मिट्टी लगायी जाती थी! गणिकाएँ वेश्याएं नहीं होती थीं बल्कि उनका काम होता था नृत्य और संगीत को माध्यम बना

कर ईश्वर की प्राप्ति। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की 565 रियासतों में से 70 से अधिक रियासतें ऐसी थीं जिनके राजा व्यक्तिगत जीवन में कुम्हार, बढ़ई, लुहार आदि थे!

आज से 200 वर्ष पहले तक भारत के गाँव सारी दुनिया के लिए भाईचारे के role models थे परंतु अंग्रेज़ों के कुछ कानूनों ने सब उलट पलट कर दिया जिससे जात पात, एक दूसरे पर शक और लाचारी ने इस व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुँचाया। आदि काल से भारत में चार वर्गों (क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र तथा वैश्य) का वर्गीकरण उनके कर्म के अनुसार किया गया था ताकि समाज का संचालन सुगठित ढंग से हो सके। अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया जिसका नाम था Indian Civil Services Act जिसमें गाँव की न्याय व्यवस्था यानी कि ग्राम पंचायत सीधे सीधे अंग्रेज़ों के अधीन हो गई। उन्होंने जिला स्तर पर कुछ लोगों की नियुक्ति की जिन्हें बोला जाता था Collector, Deputy Commissioner या District Magistrate। ये अंग्रेज़ अधिकारी न्याय तो दूर अपने भोग विलास को ध्यान में रखते हुए फैसले देते थे जिससे समाज में असंतुलन फैल गया और कुछ विशिष्ट लोगों को इनके न्याय का लाभ मिलता था जो इन अधिकारियों के शुभ चिन्तक होते थे। भारत सरकार ने इस कानून का सिर्फ नाम बदलकर Indian Administrative Act रख दिया है बाकी इसके काम करने के तरीके में कोई फेरबदल नहीं है! इसी तरह अंग्रेज़ों ने एक विभाग बनाया जिसका नाम था Public Works Department (PWD) जिसका काम था गाँव के विभिन्न विकास कार्यों की ठेकेदारी। सबसे बड़ी समस्या इस विभाग के साथ यह थी कि इसके बाबुओं को गाँव के भले बुरे का पता ही नहीं होता था क्योंकि अधिकांश या तो अंग्रेज़ होते थे या दूसरी किसी जगह के होते थे। इस विभाग के आते ही गाँव वालों के हाथ से यह अधिकार छीन लिया गया जिससे वो अब मिलजुल कर गाँव के किसी काम को अंजाम नहीं दे सकते थे चाहे वो काम कुआँ खोदना हो या सड़क बनाना हो। इस विभाग ने संगठित श्रम और एकता पर आघात किया! इसके अलावा अंग्रेज़ों ने गाँव के भले के लिए कई NGO बनाये जिनका काम था

गाँव से बेरोज़गारी और गरीबी दूर करना। बेरोज़गारी और गरीबी तो दूर हुई पर केवल इन NGO के कर्मचारियों की। इन NGO की कभी आवश्यकता थी ही नहीं क्योंकि अगर ये कानून न होते तो हमारे सारे गाँव स्वावलंबी ही तो थे! आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी देश के कई हिस्सों के हालात ऐसे हैं जहाँ एक कपड़े या साडी को कई सारी आदिवासी माताएं बहनें आपस में share करती हैं और कई स्थान तो ऐसे हैं जहाँ लोग गुठलियाँ बीन कर अपना पेट बसर करते हैं! हम में से हर भारतवासी के लिए यह बेहद शर्म का विषय है!!

जब तक ये सारे कानून नहीं बदल जाते, जब तक ये सारी व्यवस्था स्वदेशी नहीं हो जाती, तब तक भारत स्वावलंबी नहीं हो सकता।

---

काला धन भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के महाअभियान भारत स्वाभिमान से जुड़े – स्वामी रामदेव

Join movement against corruption and black money bharat swabhiman – swami ramdev

---